शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक – 24 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 3 – 10 जून 2024 मूल्य पांच रूपये

लोकसभा में मिली हार के परिणाम गंभीर होंगे

संगठन और सरकार में तालमेल के अभाव के आरोपों को मिला बल

मानहानि के मामलों पर रहेगा ध्यान केन्द्रित

सुधीर शर्मा के आरोप कितना आगे बढ़ते हैं इस पर रहेगी नजरें

क्या चुनावों में वायरल हुये वीडियोज की जांच हो पायेगी?

शिमला/शैल। कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें हार गयी हैं। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन में कांग्रेस को बढ़त नहीं दिला पाये हैं। केवल उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल बरागटा ही अपने-अपने क्षेत्र हार से बचा पाये हैं। विधानसभा अध्यक्ष और अन्य मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष तथा अन्य मुख्य संसदीय सचिव सभी भाजपा के हाथों पराजित हुये हैं। इन्हीं लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा के लिये छः उपचुनाव भी हुये थे। इनमें चार पर कांग्रेस जीत हासिल करने में सफल रही। इस चुनावी हार जीत का प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा यह इन परिणामों के बाद चर्चा और आकलन का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद उपजी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आये हैं। इसलिये कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत को लोकसभा की हार से बड़ा करार देकर अपनी पीठ थपथपा रही है। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की जनता ने सरकार और मुख्यमंत्री में विश्वास व्यक्त करते हुये सरकार को मजबूती प्रदान की है तथा सरकार शेष बचे कार्यकाल के लिये पूरी तरह सुरक्षित हो गयी है।

सरकार के इस दावे का आकलन करने के लिये राज्यसभा चुनाव में ऊभरी स्थितियों पर नजर डालने की आवश्यकता है। उस समय राज्यसभा की हार के बाद यदि बजट के समय भाजपा के विधायकों को सदन से निलंबित न किया जाता तो सरकार सदन के पटल पर ही गिर जाती। लेकिन भाजपा विधायकों के निलंबन के कारण सरकार बच गयी। बजट उसी दिन पारित करके सदन का सत्रावसान कर दिया गया। उससे स्पष्ट हो गया था कि अब सरकार का खतरा टल गया है। इसलिये निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्रों का मामला लटकाया गया। आज यदि कांग्रेस उपचुनाव में सारी सीटें भी हार जाती तो भी आंकड़ों के गणित में सरकार सुरक्षित थी। इसलिये यह कहना कि सरकार और मुख्यमंत्री को सुरक्षित करने के लिये चार उप चुनावों में कांग्रेस की जीत हुयी है यह तर्क तब पुख्ता होता यदि इन चार की जीत के साथ मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में भी कांग्रेस को बढ़त दिलाने में सफल हो जाते। यदि एक वोट सीएम और एक वोट पीएम का अमल हुआ होता तो भी सभी छः सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल होती। लेकिन ऐसा न होने से विधानसभा के इन उपचुनावों की हार जीत को भाजपा के आन्तरिक समीकरणों का प्रतिफल माना जा रहा है।

इस समय कांग्रेस 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में हारी है। जिसका अर्थ है कि यदि आज प्रदेश में किन्हीं कारणों से विधानसभा के चुनाव हो जायें तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से बन पाना कठिन है। इस चुनाव परिणाम से यह सामने आ गया है कि सरकार और संगठन में तालमेल के अभाव के जो आरोप लग रहे थे वह सही थे। इसी के साथ सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के जो आरोप लगे उन में दम था। कुछ अधिकारियों पर पत्र बम्बों के माध्यम से जो आरोप लगे उन पर सरकार की खामोशी सवालों में रही। बद्दी के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के साथ जिस तरह का व्यवहार चल रहा था उस स्थिति में उद्योग मंत्री द्वारा चीजें लगातार हाई कमान के संज्ञान में लायी जाती रही। लेकिन अन्त में जब हाईकमान थोड़ा सतर्क हुई तो एक समन्वय समिति का गठन तो कर दिया। परन्तु इसकी कोई औपचारिक बैठक तक नहीं हो पायी। कमेटी के सदस्यों ने यहां तक कह दिया कि उन्हें पूछा ही नहीं जा रहा है। यही आन्तरिक स्थितियां थीं जिनके कारण कोई लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। आर.एस.बाली को राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने में अपनी असमर्थता जाहिर करनी पड़ी। इसी वस्तु स्थिति के चलते आज बाली भी अपना चुनाव क्षेत्र नहीं बचा पाये। इन सारी स्थितियों पर निष्पक्ष राय रखने वाले स्पष्ट थे कि लोकसभा चुनावों में एक भी सीट पर सफलता मिलना कठिन है। शैल इस विषय पर स्पष्ट था कि लोकसभा में चारों सीटों पर कांग्रेस हार रही है।

अब इस चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के बगियों को जिस तरह से बिकाऊ प्रचारित किया और दावा किया कि पुलिस जांच में बहुत सारे तथ्य सामने आ गये हैं उसकी प्रतिक्रिया में बागियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि के मामले दायर कर रखे हैं। उधर बालूगंज में जो एक एफआईआर आशीष शर्मा और राकेश शर्मा के खिलाफ लंबित चल रही है उसमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा निर्दलीयों के त्यागपत्र स्वीकार करने के बाद जांच का क्या रुख उभरता है वह महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ सुधीर शर्मा अब फिर से विधानसभा में पहुंच गये हैं। जो आरोप सुधीर शर्मा ने दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाये हैं वह कितना आगे बढ़ते हैं उस पर भी सबकी नज़रें रहेगी। जो वीडियो चुनाव के अन्तिम दिनों में हमीरपुर में वायरल हुआ था शायद उसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। वह कैसे आगे बढ़ती है इस पर भी सबकी नज़रें रहेंगी। अब एक वीडियो हमीरपुर के लोकसभा उम्मीदवार रहे सतपाल रायजादा को लेकर भी वायरल हुआ है। इन सारे घटनाक्रमों को एक साथ रखकर आकलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस समय कांग्रेस के हर नेता के पास अपनी हार का एक ही जवाब है जब मुख्यमंत्री ही अपना चुनाव क्षेत्र नहीं बचा पाये तो औरों की क्या विसात थी।

अच्छे शिक्षक हर रूप में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है:राज्यपाल

शिमला/शैल। भारतीय शिक्षण मण्डल के तत्वावधान में आज राजभवन में एक राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यशाला आयोजित की गई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कार्यशाला में मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारतीय शिक्षण मण्डल एक राष्ट्रीय शैक्षणिक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। उन्होंने कहा कि इस संगठन से 5 हजार से अधिक शैक्षणिक संस्थान जुड़े हुए हैं तथा देश में इसके 50 लाख से अधिक सदस्य मौजूद हैं। उन्होंने शिक्षण मण्डल द्वारा शिक्षा तथा भाषा संशोधन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में दिए जा रहे मूल्यवान योगदान पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा सदैव हमारे समाज का मज़बूत स्तंभ रही है, जो भावी पीढ़ियों के मस्तिष्क और भविष्य को विकसित करता है। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रही हमारी दुनिया में यह आवश्यक है कि हम छात्रों की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को पूरा करने के लिए अपनी शैक्षिक प्रणालियों को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी शिक्षा और मूल्यों को बढ़ावा देने में भारतीय शिक्षण मण्डल के प्रयास उल्लेखनीय हैं जो समग्र और समावेशी शिक्षा के हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक केवल प्रशिक्षक नहीं होते, वे मार्गदर्शक और विद्यार्थियों के लिए आदर्श भी होते हैं। उन्होंने कहा कि एक अच्छे शिक्षक का प्रभाव क्लासरूम तक सीमित नहीं होता बल्कि वह हर रूप में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके द्वारा दी गई शिक्षा छात्रों के जीवन और हमारे राष्ट्र के भविष्य को प्रभावित करती है।

उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने सीखने व सिखाने के नए द्वार खोले हैं। उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों के संरक्षण के साथ तकनीकी प्रगति को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पारम्परिक मूल्यों के साथ आधुनिक शिक्षा को एकीकृत करने वाले पाठयक्रमों को बढ़ावा देने में भारतीय शिक्षण मण्डल की पहल सराहनीय है।

शुक्ल ने शिक्षकों से समाज की नींव रखने वाले नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए नवीन शिक्षण पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया।

इससे पूर्व, बेसिक एजुकेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने भारतीय शिक्षण मण्डल की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की।

राज्यपाल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज राजभवन परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने देवदार और चिनार के पौधे रोपित किए।

इस अवसर पर राजभवन और राज्य रेडक्रॉस सोसायटी के कर्मचारियों ने भी पौधे रोपे।

राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे रोपित करना सभी की नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य है। उन्होंने अधिकारियों को वनों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में पौधरोपण के लिए हर वर्ष उचित प्रबन्ध और व्यवस्था की जाती है। संबंधित विभागों को अधिक से अधिक पौधरोपण, उनकी जीवंतता एवं देखभाल सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार की दिवंगत आत्मा की स्मृति में पौधे रोपित करने चाहिए।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।

विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करें अधिकारी: विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा नाबार्ड के तहत किए जा रहे विकासात्मक कार्यो की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 व 2 के सभी कार्यो को जून 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नाबार्ड 24 और 25 भागों के कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय दावों की औपचारिकताएं जून 2024 तक पूर्ण की जाएं ताकि इन कार्यो को शीघ्र आरंभ किया जा सके।

लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को नाबार्ड भाग-29 तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-3 के कार्यो को शुरू करने के लिए स्वीकृति पत्र इस सप्ताह के अंत तक जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही सभी विकासात्मक परियोजनाओं का हर स्तर पर नियमित निरीक्षण कर इसकी रिपोर्ट प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत करनी सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यो को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूर्ण किया जाए निर्माण कार्य में देरी करने वाले ठेकेदारों के विरूध कड़ी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि अधिशाषी अभियंता स्तर पर एफआरए और एफसीए से संबंधित स्वीकृतियां लेने के मामलों की प्रक्रिया को गति प्रदान की जाए तथा निर्माण कार्यो में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए।

बैठक में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण एन.पी. सिंह, संयुक्त सचिव लोक निर्माण सुरजीत सिंह राठौर तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में 14 जून को सभी जिलों में आयोजित होगी मॉकड्रिल

शिमला/शैल। प्रदेश के सभी जिलों में 14 जून को होने जा रही आठवीं मॉकड्रिल को लेकर शिमला में आज राज्य आपदा प्रबंधन के निदेशक व विशेष सचिव डी.सी. राणा की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि व सभी जिलों के उपायुक्त शामिल हुए।

प्रदेश भर के सभी जिलों में 12 जून को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा टेबल टॉप अभ्यास किया जाएगा। टेबल टॉप अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में जमीनी स्तर पर की गई तैयारियों का मूल्याकंन करना है। 14 जून को बाढ़, भू-स्खलन, हिम-स्खलन और औद्योगिक आपदा से निपटने के लिए सभी जिलों में मॉकड्रिल की जाएगी, जिसमें विशेषकर स्कूलों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आपदा में फसे छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर अभ्यास किया जाएगा।

डी.सी. राणा ने कहा कि मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना और आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केन्द्रीय सशस्त्र बलों, पुलिस, होमगार्ड आदि में समन्वय स्थापित करना है।

उन्होंने कहा कि मॉकड्रिल के दौरान शैक्षणिक संस्थानों में राहत कैंप न बनाए जाए जिससे कि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि नदियों, झीलों और ग्लेशियर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समय से पहले ही मॉकड्रिल को लेकर की जा रही तैयारी की जानकारी दी जाए ताकि मौके पर अभ्यास के दौरान लोगों में भय का माहौल न उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि मॉकड्रिल के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ भी समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाई जाए।

उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में भी बेहद संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। ऐसे स्थानों में त्रासदी से पूर्व घटना के संबंध में जानकारी मिले इसके लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खतरनाक झीलों के किनारे रह रही आबादी के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने पर भी बल दिया जाए। आपात स्थिति में किसी भी त्रासदी की जानकारी मिलने पर मौके पर जमीनी स्तर पर अपनी कार्य योजना को भी लागू करने के लिए विकल्प रखें।

उन्होंने कहा कि इस मॉकड्रिल में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन का त्रिस्तरीय समन्वय होगा। डी.सी. राणा ने बताया कि इस बार मॉकड्रिल में संचार सुविधा बाधित हो जाने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास भी किया जाएगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विशेष तौर पर नेतृत्व कर रहे सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुधीर बहल ने आपदा से निपटने के लिए विशेष योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

आगामी सेब सीजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राज्य सरकार आगामी सेब सीजन के दौरान फल उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए यूनिवर्सल कार्टन की शुरूआत सुनिश्चित करेगी। यह बात बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विभिन्न हितधारकों के साथ सेब सीजन की तैयारियों के तैयारियों के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सेब सीजन के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार सेब सीजन को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सभी हितधारकों के लाभ के लिए राज्य में यूनिवर्सल कार्टन का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सेब उत्पादकों से किए गए वायदे को पूरा करने के लिए पिछले साल वजन किलोग्राम के हिसाब से सेब की बिक्री शुरू की गई थी। उन्होंने फल व्यापारियों के पंजीकरण और उनको लाइसेंस देने तथा फल उत्पादकों को समय पर भुगतान करने पर भी बल दिया।

जगत सिंह नेगी ने शिमला जिला प्रशासन को मांग के अनुसार फलों की पेटियों के परिवहन के लिए ट्रकों और पिकअप वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा किलोग्राम और किलोमीटर के आधार पर सेब के परिवहन के लिए माल ढुलाई शुल्क निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फागू में मुख्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पुलिस विभाग को सेब सीजन के दौरान यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग को फल उत्पादक क्षेत्रों को टर्मिनल मंडियों से जोड़ने वाली सड़कों के उचित रखरखाव और भारी बारिश और भूस्खलन से बाधित सड़कों को समय पर बहाल करने के निर्देश दिए गए।

हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक सुदेश कुमार मोखटा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और आश्वासन दिया कि सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी, संयुक्त सचिव बागवानी विक्रम सिंह नेगी, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लिमिटेड हिमफेड के प्रबंध निदेशक ज्ञान सागर नेगी, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि एवं विपणन बोर्ड एचपीएसएएमबी के प्रबंध निदेशक हेमिस नेगी, सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण नरेश ठाकुर, मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच लोक निर्माण विभाग सुरेश कपूर तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नौणी विश्वविद्यालय ने स्नातक कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जून तक बढ़ाई

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अपने स्नातक कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जून तक बढ़ा दी है।

स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जून और स्व-वित्तपोषित सीटों के लिए 28 जून है। स्नातकोत्तर प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 20 जून है। स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम की प्रवेश परीक्षा की तारीख क्रमश: 16 जून और 5 जुलाई है। प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 12 जून से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। स्नातक प्रवेश परीक्षा का परिणाम 25 जून को घोषित किया जाएगा जबकि स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का परिणाम 11 जुलाई को घोषित किया जाएगा। स्नातक स्व-वित्तपोषण सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची 1 जुलाई को प्रदर्शित की जाएगी। स्नातक प्रवेश परीक्षा सोलन, हमीरपुर, सुंदरनगर, पालमपुर और रामपुर में आयोजित की जाएगी।

बागवानी, वानिकी, प्राकृतिक खेती, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी और कृषि-व्यवसाय जैसे विविध क्षेत्रों में पढ़ाई करने के रुचि रखने वाले भावी छात्र आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.yspuniversity.ac.in पर लॉग इन करके आवेदन कर सकते हैं। सभी कार्यक्रमों की विस्तृत विवरणिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में स्थित बागवानी महाविद्यालय,वानिकी महाविद्यालय और नेरी और थुनाग में बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालयों के एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, नेरी और थुनाग महाविद्यालयों में बीएससी(ऑनर्स) बागवानी और बी एससी(ऑनर्स)वानिकी कार्यक्रमों के लिए आवेदन किया जा सकता हैं। छात्रों को मुख्य परिसर में बीएससी (ऑनर्स) प्राकृतिक कृषि और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी स्व-वित्तपोषण, में आवेदन करने का भी विकल्प है। विश्वविद्यालय के नेरी महाविद्यालय में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।

विश्वविद्यालय ने नौणी स्थित बागवानी महाविद्यालय और वानिकी महाविद्यालय और नेरी महाविद्यालय में एमएससी कार्यक्रमों की भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एम.बी.ए. एग्री-बिजनेस मैनेजमेंट और एमटेक फूड टेक्नोलॉजी के कोर्स भी छात्रों को ऑफर किए जा रहे हैं।

स्नातक प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर स्नातक कार्यक्रमों की सामान्य सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। जबकि स्नातक की स्व वित्त पोषित सीटों पर प्रवेश 10+2 परीक्षा में चार विषयों- अंग्रेजी, फ़िज़िक्स, कैमिस्ट्रि और बायोलॉजी/ गणित की मेरिट के आधार पर होगा। स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। आवेदक सामान्य एवं स्ववित्तपोषित दोनों प्रकार की सीटों के लिए आवेदन कर सकता है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई, भूतल परिवहन मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की जा रही विभिन्न फोरलेन परियोजनाओं तथा अन्य निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं के कार्य की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने विभागों को विकासात्मक कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों को शिमला-मटौर तथा मंडी-पठानकोट सड़कों को पूर्ण रूप से फोरलेन में विकसित करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल सके। राज्य सरकार कांगड़ा जिला को राज्य की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है तथा दोनों फोरलेन परियोजनाएं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने दोनों फोरलेन परियोजनाओं की सुंदरता बढ़ाने तथा अनावश्यक रूप से पहाड़ियों को काटने के लिए सुरंगों के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फोरलेन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यात्रियों के समय तथा धन की बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला से नौणी सड़क का निर्माण कार्य इस वर्ष मानसून के बाद शुरू किया जाएगा। सितंबर, 2026 तक इस कार्य के पूरा होने की उम्मीद है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिंजौर-नालागढ़-बद्दी फोरलेन के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी ताकि इस क्षेत्र में उद्योगों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने इस परियोजना को वर्ष 2025 के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला बाईपास परियोजना, शिमला-सोलन फोरलेन व मंडी-हमीरपुर और पांवटा-शिलाई सड़कों को चौड़ा करने और इनके सुदृढ़ीकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार और अमनदीप गर्ग, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी अब्दुल बासित, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता एन.पी. सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नरेन्द्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि श्री मोदी देश और प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए उदार वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। प्रदेश उदार वित्तीय सहायता से लाभान्वित होगा, जिसका उपयोग राज्य की अधोसंरचना और समग्र विकास के लिए किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने जगत प्रकाश नड्डा को भी केंद्रीय मंत्रिमण्डल में शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि श्री नड्डा प्रदेश की कठिन भौगोलिक स्थितियों से भली-भांति परिचित हैं और उन्होंने आशा व्यक्त की कि वह प्रदेश के लोगों की विकासात्मक मांगों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे।

समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी देगा हिमाचल: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार के साथ किये गये समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के बारे में कहा कि इन क्षेत्रों में मतदाओं द्वारा निर्दलीय विधायक चुने गये थे जो विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार या विपक्ष का साथ दे सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सदस्यता को त्यागने का निर्णय किस आधार पर लिया है, यह बात उन्हें जनता के सामने रखनी चाहिये। यह बात स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी सदस्यता को निजी लाभों के लिये दांव पर लगाया है। यह भी देखना होगा कि क्या भाजपा इन पूर्व तीन निर्दलीय विधायकों को अपना उम्मीदवार घोषित करती है या नहीं। उन्होंने कहा कि इन तीन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता इन पूर्व विधायकों से यह प्रश्न करेंगे कि जब उन्हें पांच वर्षों के लिए अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था तो फिर उन्होंने किन कारणों के चलते राज्य पर उपचुनाव का बोझ डाला गया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर हुये आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में अब तक 9 लोगों की मृत्यु हुई है।

प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट मनी में की वृद्धि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश को खेल भूमि बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश के कोने-कोने से खेल प्रतिभाओं की खोज कर उनकी प्रतिभा को निखारा जा रहा है।

राज्य सरकार ने प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करने के साथ-साथ खिलाड़ियों को मिलने वाले डाइट मनी और यात्रा प्रावधानों में वृद्धि की है।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए डाइट मनी को 240 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये, जिला स्तरीय खेल आयोजनों के लिए 300 रुपये और खंड स्तरीय आयोजनों के लिए 240 रुपये किया गया है। प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाली खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी को 500 रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त खेल छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों को प्रारंभिक शिक्षा स्तर तक 250 रुपये तथा अन्यों को 400 रुपये की डाइट मनी का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले खेल आयोजनों में भाग लेने वालों खिलाड़ियों को मिलने वाले यात्रा प्रावधानों में भी वृद्धि की है। इस सुविधा के अन्तर्गत 200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए खिलाड़ियों को एसी-थ्री टियर रेल किराया तथा 200 किलोमीटर से अधिक यात्रा करने वाले खिलाड़ियों को इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार के यह प्रयास दर्शाते हैं कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुने जाने पर सोनिया गांधी को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके असाधारण नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी ने अनेक चुनौतियों पर विजय हासिल की है। उनकी दूरगामी सोच, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता और सामाजिक न्याय के लिए किए गए अथक प्रयासों ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनसेवा और संविधान में निहित सिद्धांतों की रक्षा के अभियान को मिशन मोड में जारी रखेगी।

बनखंडी वन्य प्राणी उद्यान का पहला चरण जून 2025 में होगा पूर्ण

शिमला/शैल। हिमाचल में पर्यटन के बहुआयामी महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार राज्य में विस्तृत स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार राज्य में धार्मिक, साहसिक, रोप-वे, जलक्रीड़ा गतिविधियों, एयरो स्पोर्ट्स पर्यटन के साथ-साथ अत्याधुनिक अधोसंरचना निर्मित करने पर बल दे रही है।

इस कड़ी में जिला कांगड़ा के देहरा उप-मंडल के बनखंडी में निर्मित किए जा रहे दुर्गेश अरॉय वन्य प्राणी उद्यान का पहला चरण जून, 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। यह प्राणी उद्यान 180 हेक्टयेर में फैला हुआ है और लगभग 619 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 3 वर्ष के भीतर तीन चरणों निर्मित किया जाएगा। यह प्राणी उद्यान क्षेत्रा के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके निर्माण के लिए 24 मई, 2024 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राणी उद्यान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिमुडा बाढ़बंदी कार्य तथा जल संरक्षण गतिविधियों और जल निकासी व्यवस्था जैसे कार्य सुनिश्चित करेगा।

इस प्राणी उद्यान में वॉक-इन-एवियरी, मोनोरेल सफारी, वॉक-इन-एक्वेरियम, नेचुरल ट्रेल पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। प्रथम चरण के अन्तर्गत आगन्तुकों के लिए बाघ और शेर के बाड़े तैयार किए जाएंगे। द्वितीय एवं तृतीय चरण के अन्तर्गत भालू और तेन्दुए की सफारी की भी सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा हिम तेन्दुओं के लिए अलग से खंड बनाने की योजना तैयार की जा रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सैलानियों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान के प्रवेश द्वार पर स्थानीय जीवन शैली को प्रदर्शित करती हुई कांगड़ा गांव की एक प्रतिकृति स्थापित की जाएगी। लोगों की सुविधा के लिए पर्याप्त पार्किंग, इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। प्राणी उद्यान में आने वाले लोगों और जानवरों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए वन विभाग को स्थानीय प्रजाति के पेड़-पौधे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह प्राणी उद्यान जिला कांगड़ा को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करने में मील पत्थर साबित होगा और इससे क्षेत्र में पर्यटकों के आगमन में बढ़ोतरी होगी।

शहरी विकास मंत्री ने शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान विश्व बैंक की टीम ने विक्रमादित्य सिंह को शिमला जलापूर्ति तथा सीवरेज कार्यक्रम पर शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित खर्च से किए जा रहे कार्यों के बारे अवगत करवाया। टीम ने 872 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जा रही निर्बाध जलापूर्ति परियोजना के संचालन तथा रखरखाव की अवधि 15 साल बढ़ाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए गए विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा की गई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार इन कार्यों को और बेहतर बनाने के लिए वचनबद्ध है।

प्रधान सचिव, शहरी विकास देवेश कुमार ने प्रदेश में मण्डी, धर्मशाला, सोलन तथा पालमपुर नगर निगमों में शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के विस्तार से सम्बंधित जानकारी मंत्री को दी। इस निर्णय के कार्यान्वयन के उपरांत शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को हिमाचल जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाएगा।

विश्व बैंक की टीम का नेतृत्व कार्मन तथा तनुज माथुर ने किया। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वीरेंद्र सिंह ठाकुर, महाप्रबंधक राजेश कश्यप तथा निदेशक शहरी विकास गोपाल चंद भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

यह टीम मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के साथ भी बैठक करेगी।

पांच साल चलेगी कांग्रेस सरकार:अनिरूद्ध सिंह

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान कांग्रेस सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और भाजपा सरकार बनाने की तारीख पर तारीख दे रहे हैं।

अनिरूद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को पांच साल तक हिमाचल प्रदेश में सरकार चलाने का जनादेश दिया है और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मजबूत है। उपचुनाव की चार सीटें जीतने के बाद विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है और प्रदेश के मतदाताओं ने खरीद-फरोख्त की राजनीति को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा ने धनबल से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया, वहां भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि देशभर में भाजपा की खरीद-फरोख्त की राजनीति मतदाताओं को रास नहीं आयी है और भाजपा को इससे सबक सीखना चाहिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि 4 जून को दो सरकारें बनाने के जय राम ठाकुर के दावे धरे के धरे रह गये। उन्होंने कहा कि भाजपा का 400 पार का नारा भी फेल हो गया, जिससे साबित होता है कि भाजपा से देश की जनता का मोहभंग हो गया है। उन्होंने कहा कि अब एनडीए सरकार में सहयोगी दलों ने भी भाजपा को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है।

जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है – शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक उसे जहर की तरह त्याग दो।

.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

मोदी का तीसरा कार्यकाल –कुछ उभरते सवाल

नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद पहले नेता हैं। इसके लिये वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र है लेकिन इस बार वह एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा को अपने दम सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिल पाया है। इसलिये माना जा रहा है कि इस बार वह लगातार अपने सहयोगियों के दबाव में रहेंगे। इस बार भी चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़े गये। हर चुनावी वायदे को मोदी की गारंटी बनाकर परोसा गया। लेकिन यह गारंटियां भी पहले जितनी सफलता नहीं दिला पायी। ऐसा क्यों हुआ और इस पर भाजपा की समीक्षा के बाद क्या जवाब आयेगा इसका पता आने वाले दिनों में लगेगा। मोदी ने देश की सता 2014 में संभाली थी। 2014 और 2019 में जो वायदे देश के साथ मोदी भाजपा और एनडीए ने किये थे यह 2024 का चुनाव इन वायदों की परीक्षा था और उस परीक्षा में निश्चित रूप से यह सरकार सफल नही हो पायी है। इस बार विपक्ष भी पहले से कहीं ज्यादा सशक्त होकर उभरा है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि इस बार जनता ने एक सशक्त विपक्ष के लिये मतदान किया है। विपक्ष ने चुनाव प्रचार के दौरान जो तीखे सवाल सरकार से पूछे और सरकार उन सवालों का जब जवाब नहीं दे पायी उससे जनता का विश्वास विपक्ष पर बना तथा एक ताकतवर विपक्ष देश को मिला। जिस विपक्ष पर यह तंज कसा जाता था कि इस बार वह संख्या में पहले से भी कम होगा तो वह विपक्ष इस बार दो गुना होकर उभरा है। इसलिये यह माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष की आवाज को सदन के भीतर दबाना आसान नहीं होगा। क्योंकि मतदान के अंतिम चरण के साथ ही जब एग्जिट पोल के परिणाम आये और उनकी खुशी में प्रधानमंत्री गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने शेयर बाजार में अप्रत्याशित बढ़त आने के अनुमान लगाये तो उससे बाजार में बढ़त देखने को मिली। लेकिन जैसे ही वास्तविक चुनाव परिणाम आये तो शेयर बाजार धड़ाम से नीचे बैठ गया और एक दिन में ही निवेशकों का तीस लाख करोड़ डूब गया। शेयर बाजार के इस उतार चढ़ाव पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिये। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है और शीर्ष अदालत में इसका संज्ञान लेते हुए संबद्ध पक्षों से जवाब भी मांग लिया है। यही स्थिति नीट की परीक्षा को लेकर सामने आयी हैं और शीर्ष अदालत ने इस पर भी सवाल पूछ लिये हैं। पैगासैस पर संयुक्त संसदीय कमेटी की जांच की मांग उठ चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि 2014 से लेकर आज तक जो भी गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे संसद के शोर में दबकर रह गये हैं उन पर अब संसद में चर्चा अवश्य होगी। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोग अब तक विदेश से क्यों वापस नहीं लाये जा सके हैं इसका जवाब देश की जनता के सामने आयेगा। इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति तो संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के ब्यान से उभरी है। इस चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा में संघ भाजपा के रिश्तों के बीच जो लकीर खींचने का प्रयास किया था संघ प्रमुख के ब्यान को उस लकीर का जवाब माना जा रहा है। इस बार जिस तर्ज पर विपक्ष के लोगों को तोड़कर भाजपा में शामिल करने का अभियान चलाया गया और इस अभियान में ज्यादा फोकस कांग्रेस पर था। यदि इस अभियान के माध्यम से कांग्रेस को कमजोर दिखाने की रणनीति न रही होती तो शायद एनडीए मिलकर भी सरकार बनाने की स्थिति में न आ पाता। लेकिन इस रणनीति से जो भाजपा का वैचारिक धरातल पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। संघ प्रमुख का ब्यान इसी बिन्दु से जुड़े सवाल माना जा रहा है। क्योंकि इस ब्यान में उठाये गये सवाल एक लंबे अरसे से जवाब मांग रहे थे जिन्हें अब तक सशक्त स्वर नहीं मिला है।

तो क्या इस बार के संसदीय आम चुनाव को US लॉबी ने प्रभावित किया?

गौतम चौधरी

अभी हाल ही में संपन्न संसदीय आम चुनाव का परिणाम आते ही प्रतिपक्ष, खास कर कांग्रेस नरेन्द्र मोदी पर हमलावर हो गयी। राहुल व प्रियंका सहित कई नेताओं ने नरेन्द्र मोदी को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और यहां तक कह दिया कि उनको भारत की जनता ने नकार दिया है, इसलिए तुरंत प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ राजनीति से सन्यास ले लेना चाहिए। हालांकि नरेन्द्र मोदी की अगुआई वाली भाजपा इस बार भी उतनी सीट ले आयी, जितनी कांग्रेस को बीते तीन चुनाव जोड़ कर भी नहीं आयी है। इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में किया है। बावजूद इसके 2024 के संसदीय आम चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निःसंदेह बढ़िया रहा है।

इस बार कांग्रेस को 2019 की तुलना में दोगुना के करीब सीटें आयी है। यह कांग्रेस का सराहनीय प्रदर्शन है, जबकि भाजपा की सीटें घटी है और 2019 की तुलना में भाजपा को 63 सीटों का नुकसान हुआ है। यदि प्रतिशत में बात करें तो 2019 की तुलना में इस बार भाजपा को 6 प्रतिशत वोट कम मिले हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का है। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं लेकिन इस हार को लेकर विदेशी ताकतों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पहले जब चुनाव को प्रभावित करने को लेकर विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप के आरोप लगते थे तो निशाने पर सत्ता पक्ष होता था। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2014 और 2019 के संसदीय आम चुनाव में प्रतिपक्षी कई पार्टियों ने भाजपा के ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका से सहयोग प्राप्त कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। इससे पहले 2009 में खुद कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने वाली साम्यवादी पार्टियों ने चुनाव में बाहरी शक्तियों से सहयोग प्राप्त कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। 2009 में संसदीय चुनाव हुआ तो डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस 2004 की तुलना में और ज्यादा मजबूती से वापस आयी। इससे पहले भी सोवियत रूस के समर्थन से चुनाव जीतने का आरोप श्रीमती इंदिरा गांधी पर लगा था लेकिन इस बार के चुनाव में प्रतिपक्षी पार्टियों पर उंगली उठ रही है। खास कर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर भारतीय चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लग रहा है।

इस बार के चुनाव को लेकर अमेरिका स्थित एक थिंकटैंक ने अपने बयान में कहा था कि 2024 के संसदीय आम चुनाव को चीन की खुफिया एजेंशी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उसी समय भारतीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए और देशी एजेंसियां चौकन्नी हो गयी थी। ऐन चुनाव प्रक्रिया के दौरान कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान के समर्थन में न केवल बयान आया, अपितु उन्होंने खुले तौर पर खलिस्तानियों के कार्यक्रम में जाकर भौतिक रूप से उन्हें समर्थन दिया। पाकिस्तान के बाद कनाडा दूसरा ऐसा देश है जो खुलेआम भारत की अखंडता पर चोट करने वाले आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहा है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक चुनाव के दौरान ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत के खिलाफ बयान जारी किया और कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के हितों पर चोट पहुंचाया जा रहा है और वहां के अल्पसंख्यक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के एक थिंक टैंक ने मणिपुर में हो रही घटनाओं पर नकारात्मक टिप्पणी की। इन तमाम घटनाओं और बयानों को चुनाव प्रभावित करने और भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। 4 जून को मत गिनती के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन कमजोर प्रदर्शन कर रहे थे तो एक बार फिर कनाडा के राष्ट्रपति ने कहा, भारत में नरेंद्र मोदी की जीत लोकतंत्र के लिए खतरा है।

यूएस लॉबी के ये तमाम बयान और गतिविधियां यह साबित करने के लिए काफी है कि उनकी नजरों में नरेंद्र मोदी और भारत का समावेशी राष्ट्रवादी उभार खटक रहा है। इसलिए उन्होंने मोदी की नकारात्मक छवि गढ़ने की कोशिश की। लेकिन इतना होने के बाद भी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं।

अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिकी लॉबी को मोदी क्यों खटक रहे हैं? इस सवाल का जवाब सरल है। मसलन, मोदी ने ब्रिक्स को मजबूत करने में रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील का साथ दिया है। शंघाई सहयोग संगठन के वैश्विक विस्तार में सहयोग किया है। डॉलर की दादागिरी पर लगाम लगाने में सऊदी अरब, चीन, रूस, ब्राजील, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, दक्षिण एशिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देश का सहयोग किया है। रूस–यूक्रेन संघर्ष में तटस्थ भूमिका निभाई। फिलिस्तीन–इजरायल संघर्ष में पारंपरिक विदेश नीति के तहत फिलिस्तीन का साथ दिया। कोरोना महामारी के दौरान सन फार्मा जैसी अमेरिकी कंपनी को देश में घुसने नहीं दिया और अपना वैक्सीन बना कर न केवल देश को सुरक्षित किया अपितु दुनिया के कई देशों को सस्ते में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराया। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला कंपनी को अपनी शर्त मानने को विवश किया। ये ऐसे तमाम कारक हैं, जिसके कारण पश्चिम की नजरों में मोदी खटकने लगे हैं। यही कारण है कि विपक्षी गठबंधन को जमीन तैयार करने में अमेरिकी की भूमिका संदिग्ध दिख रही है। इस काम में अमेरिकी कंपनियों के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया ने भारत में व्यापार खेल खेला। चूंकि पारंपरिक समाचार माध्यम देशी पूंजी के प्रभाव में हैं इसलिए गैर पारंपरिक मीडिया को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में सहयोग दिया गया। यह देखने में सामान्य–सा दिखता है लेकिन इसके पीछे बड़ा तंत्र काम कर रहा है।

ऐसा इसलिए किया गया कि मोदी चुनाव हार जाएं और यदि चुनाव नहीं हारें तो कम से कम उनकी सरकार कमजोर हो और उन्हें निर्णय लेने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इस काम में इस बार भाजपा के कुछ समान विचारधारा वाले संगठनों ने भी जाने अंजाने विदेशी शक्तियों को सहयोग किया है। हालांकि भाजपा का चुनाव में बुरा प्रदर्शन के लिए और कई कारक जिम्मेदार है, उसमें भाजपा की वह नीतियां भी शामिल है, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है लेकिन उन नीतियों को हवा देना और उसके खिलाफ आम लोगों से लेकर खास तक को गोलबंद करने में विदेशी ताकत खास कर अमेरिकी लॉबी की बड़ी भूमिका साफ नजर आ रही है।

राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यो को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई

शिमला। भारत के राष्ट्रपति ने नरेन्द्र दामोदरदास मोदी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद के सदस्यो को नियुक्त कर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), 36 राज्य मंत्री शामिल है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यो को विभागों का आवंटन किया गया है।

प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री तथा निम्न मंत्रालयों के प्रभारी: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, और अन्य सभी विभाग, जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री

1. श्री राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री)
2. श्री अमित शाह (गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री)
3. श्री नितिन जयराम गडकरी (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री)
4. श्री जगत प्रकाश नड्डा (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री)
5. श्री शिवराज सिंह चौहान (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री)
6. श्रीमती निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री)
7. डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर(विदेश मंत्री)
8. श्री मनोहर लाल(आवासन और शहरी कार्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री)
9. श्री एच. डी. कुमारस्वामी (भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री)
10. श्री पीयूष गोयल(वाणिज्य और उद्योग मंत्री)
11. श्री धर्मेंद्र प्रधान (शिक्षा मंत्री)
12. श्री जीतन राम मांझी (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री)
13. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (पंचायती राज मंत्री, तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री)
14. श्री सर्बानंद सोनोवाल (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री)
15. डॉ. वीरेंद्र कुमार(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री)
16. श्री किंजरापु राममोहन नायडू (नागर विमानन मंत्री)
17. श्री प्रल्हाद जोशी (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री)
18. श्री जुएल ओराम (जनजातीय कार्य मंत्री)
19. श्री गिरिराज सिंह(वस्त्र मंत्री)
20. श्री अश्विनी वैष्णव(रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री)
21. श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया(संचार मंत्री, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री)
22. श्री भूपेंद्र यादव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री)
23. श्री गजेंद्र सिंह शेखावत(संस्कृति मंत्री, तथा पर्यटन मंत्री)
24. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी(महिला एवं बाल विकास मंत्री)
25. श्री किरेन रिजिजू (संसदीय कार्य मंत्री, तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री)
26. श्री हरदीप सिंह पुरी(पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री)
27. डॉ. मनसुख मंडाविया(श्रम एवं रोजगार मंत्री, तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री)
28. श्री जी. किशन रेड्डी (कोयला मंत्री, तथा खान मंत्री)
29. श्री चिराग पासवान(खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री)
30. श्री सी. आर. पाटिल(जल शक्ति मंत्री)

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1. राव इंद्रजीत सिंह (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री)
2. डॉ. जितेंद्र सिंह (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री।
3. श्री अर्जुन राम मेघवाल(विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री)
4. श्री जाधव प्रतापराव गणपतराव (आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री)
5. श्री जयंत चौधरी(कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री)

राज्य मंत्री

1. श्री जितिन प्रसाद (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री)
2. श्री श्रीपद येसो नाइक (विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री)
3. श्री पंकज चौधरी(वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री)
4. श्री कृष्ण पाल(सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री)
5. श्री रामदास अठावले(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री)
6. श्री राम नाथ ठाकुर(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री)
7. श्री नित्यानंद राय(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री।
8. श्रीमती अनुप्रिया पटेल(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राज्य मंत्री, और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री)
9. श्री वी. सोमन्ना(जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री)
10. डॉ.चंद्र शेखर पेम्मासानी(ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री)
11. प्रो.एस. पी. सिंह बघेल(मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री)
12. सुश्री शोभा करंदलाजे(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री, और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री)
13. श्री कीर्तिवर्धन सिंह(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री, और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री)
14. श्री बी. एल. वर्मा(उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री)
15. श्री शांतनु ठाकुर(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री)
16. श्री सुरेश गोपी(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री, और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री)
17. डॉ. एल. मुरुगन(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री)
18. श्री अजय टम्टा(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री)
19. श्री बंदी संजय कुमार(गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री)
20. श्री कमलेश पासवान(ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री)
21. श्री भागीरथ चौधरी(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री)
22. श्री सतीश चंद्र दुबे (कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री, और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री)
23. श्री संजय सेठ(रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री)
24. श्री रवनीत सिंह (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री)
25. श्री दुर्गादास उइके(जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री)
26. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे(युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री)
27. श्री सुकांत मजूमदार(शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री)
28. श्रीमती सावित्री ठाकुर (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री)
29. श्री तोखन साहू(आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री)
30. श्री राज भूषण चौधरी(जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री)
31. श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा (भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री)
32. श्री हर्ष मल्होत्रा(कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री)
33. श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री।
34. श्री मुरलीधर मोहोल(सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री)
35. श्री जॉर्ज कुरियन(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री)
36. श्री पबित्रा मार्गेरिटा(विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री)

विश्व पर्यावरण दिवस - 2024

भारतीय नौसेना, एक पूर्ण विकसित 'ग्रीन फुटप्रिंट वाली ब्लू वाटर फोर्स'

शिमला। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बल के रूप में भारतीय नौसेना ने अक्षय ऊर्जा की ओर तीव्र बदलाव करने और यथासंभव जीवनशैली से जुड़ी कार्य प्रणालियों को अपनाकर अपने पर्यावरणीय फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हरित पहल हमेशा से भारतीय नौसेना के प्रमुख फोकस क्षेत्रें में से एक रही है। हमारे देश की ऊर्जा नीति में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से कम कार्बन उत्सर्जन की रणनीति में बदलाव के साथ, सभी नौसेना इकाइयों और प्रतिष्ठानों को 'स्वच्छ और हरित' पर्यावरण की ओर प्रगतिशील परिवर्तन का संकेत देने वाली विविध गतिविधियां करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय भूमि की गुणवत्ता की पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने के समाधानों पर केंद्रित है। समुद्री क्षेत्र में इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए, वृक्षारोपण, मैंग्रोव संरक्षण (2023 के मिष्टी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में), कार्बन फुटप्रिंट में कमी, तटीय क्षेत्रों से प्लास्टिक निपटान और पुनर्प्राप्ति, मैंग्रोव वृक्षारोपण पर नई पहल, समुद्री शैवाल की खेती, प्रवाल भित्ति सर्वेक्षण सभी को सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के निकायों और बड़ी संख्या में सरकार द्वारा नामित और पर्यावरण के प्रति जागरूक फर्मो के साथ घनिष्ठ संपर्क में लाया गया है।

भारतीय नौसेना ने तटीय इकोसिस्टम के कायाकल्प और लुप्तप्राय देशी समुद्री प्रजातियों के संरक्षण पर सहयोग आधारित प्रयासों के लिए मार्च 23 में एचसीएल फाउंडेशन और द हैबिटेट्स ट्रस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और कई कार्यक्रमों का समन्वय किया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: -

करवार में जैव विविधता सर्वेक्षण।

पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों में जैव-विविधता पार्क और पगडंडियों का निर्माण।

चरणबद्ध पुनर्स्थापना के लिए अंजेदिवा द्वीप की पारिस्थितिक बहाली और भूभाग मानचित्रण का कार्य प्रगति पर है।

स्थानीय गैर-सरकारी संगठन, रिसर्च एंड एनवायरनमेंटल एजुकेशन फाउंडेशन (आरईईएफ) के सहयोग से लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल पुनर्स्थापना योजना।

विशाखापत्तनम और कोच्चि में विभिन्न स्थानों पर फर्म मेसर्स अल्फा एमईआरएस के सहयोग से फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर की स्थापना का प्रस्ताव।

प्रारंभिक जैव विविधता सर्वेक्षण करने के लिए आईएनएस चिल्का का दौरा संपन्न हुआ।

वर्दीधारी कार्मिकों के रूप में, पर्यावरण चेतना की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प हमारे मूल में समाहित है और एक टीम के रूप में, भारतीय नौसेना ने अपने अटूट उत्साह को जारी रखने और उस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है।

हरित जीवन शैली को अपनाने के अंतर्निहित महत्व के साथ, भारतीय नौसेना ने भारत सरकार की पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ) पहल के अनुरूप संगठनात्मक और व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छ और हरित कार्य प्रणालियों को अपनाने को प्राथमिकता दी है। ऑक्यूपेंसी सेंसर और स्वचालित नियंत्रक के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा की बचत, सौर परियोजनाओं के माध्यम से अक्षय ऊर्जा का संवर्धन, ई-वाहनों पर जोर देते हुए वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी, नौसेना प्रतिष्ठानों के भीतर नो-व्हीकल डे का पालन, जल संरक्षण उपाय और कार्बन फुटप्रिंट में कमी और नए निर्माण भवनों के लिए गृह III मानदंडों का पालन करना इन कदमों में शामिल है।

'स्वच्छ भारत अभियान' के विजन को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नौसेना ने पुनीत सागर अभियान (पीएसए) कार्यक्रम के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान प्लास्टिक और अन्य कचरे के समुद्री तटों/समुद्र तटों की सफाई और उन्हें स्वच्छ, शांत और प्राचीन रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी केंद्रित है। स्थानीय नौसैनिक इकाइयां और प्रतिष्ठान नदियों/झीलों सहित तटीय सफाई के लिए हर महीने एक दिन समर्पित करते हैं और अपशिष्ट पदार्थो के जिम्मेदार निपटान/ रीसाइक्लिंग के लिए स्थानीय नगर निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के क्षेत्रीय निदेशकों के साथ संपर्क करते हैं।

पहली पहल के रूप में, डीजल इंजन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए मेसर्स चक्र इनोवेशन द्वारा विकसित स्वदेशी मेक और पेटेंटेड रेट्रोफिट डिवाइस को लंबी अवधि के परीक्षणों के लिए तट-आधारित डीजल जेनरेटर पर स्थापित किया गया था। भविष्य में हाइड्रोजन फेरी क्राफ्ट को शामिल करने की भी योजना है, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके।

भारत सरकार की जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) पहल के अनुरूप, नौसेना में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठानों ने सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण जैसे कि सौर जल हीटर, सौर स्ट्रीट लाइटिंग, सौर कुकर आदि स्थापित किए हैं।

सफल कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी के बल पर की गई की गई पहलों की बड़ी भूमिका है। भारतीय नौसेना में हरित उपायों की स्थापना एक आत्म-जागरूक नौसेना समुदाय के माध्यम से संभव हुई है, जो पर्यावरण सुधार और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता से अच्छी तरह परिचित है। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए, सामूहिक श्रमदान, तटीय सफाई अभियान, वृक्षारोपण अभियान, वॉकथॉन आदि जैसे विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

महासागर सफाई गतिविधियों का हिस्सा बनने के लिए फर्मो को शामिल करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। आने वाले वर्षो में इस गतिविधि के फलीभूत होने की संभावना है। इस बीच, अभिनव लेकिन सरल तरीकों से समुद्री जल प्लास्टिक अपशिष्ट सफाई करने के लिए आत्मनिर्भर तरीके अपनाए गए हैं।

कुल मिलाकर, नौसेना हमारे देश के ऊर्जा और पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह अब एक पूर्ण विकसित 'ग्रीन फुटप्रिंट वाली ब्लू वाटर फोर्स' है और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण बनाने में अपनी भूमिका के प्रति पूरी तरह सजग है।

शिमला में सर्कुलर रोड पर नवबहार से चिकित्सा महाविद्यालय तक बनाई जाएगी 890 मीटर सुरंगःमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। शिमला शहर में यातायात की समस्या के निवारण के लिए राज्य सरकार जाखू पहाड़ी के नीचे नव बहार पेट्रोल पंप के समीप से सर्कुलर रोड पर चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तक 890 मीटर लंबी डबल लेन सुरंग का निर्माण करेगी। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग का निर्माण 295 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा, जिसमें से 100 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं और इस माह के अंत तक निविदा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिमला शहर में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है, ताकि स्थानीय लोगों के साथ-साथ यहां भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग को वाहनों का सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सर्कुलर रोड़ पर सभी बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। इसके दृष्टिगत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्कुलर रोड़ को चौड़ा एवं सुदृढ़ करने के लिए 122 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पार्किंग से संबंधित आधारभूत ढांचे को भी सुदृढ़ किया जाएगा तथा 3000 अतिरिक्त वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा सृजित की जाएगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला शहर में ओवरहेड तारों को हटाने की योजना पर दृढ़ता से कार्य कर रही है। इसके दृष्टिगत विद्युत केबल और ऑप्टिकल फाइबर के लिए भूमिगत डक्ट बिछाई जाएंगी। इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में माल रोड, लोअर बाजार तथा मिडिल बाजार क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाएगा और लगभग 23 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सभी परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिये, ताकि प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया जा सके।

बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक हरीश जनारथा, प्रधान सचिव देवेश कुमार तथा डॉ. अमनदीप गर्ग, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण एन.के. सिंह, प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन, राजीव कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इलैक्ट्रिक बसों के लिए 517 करोड़ रुपये का बजटः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निगम के संचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम द्वारा 25 नई वॉल्वो बसें तथा 50 टैम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम के बेड़े में इलैक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिनके प्रापण के लिए प्रक्रिया जारी है। वर्तमान वित्त वर्ष में इलैक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 517 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

प्रदेश में सीमित हवाई तथा रेल नेटवर्क के दृष्टिगत निगम की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम के संचालन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को 63 प्रतिमाह करोड़ रुपये प्रदान करेगी।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में इलैक्ट्रिक बसों की विशेष भूमिका रहेगी।

बैठक में प्रधान सचिव परिवहन आर.डी.नज़ीम, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा भी उपस्थित थे।

राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि ओलम्पिक, शीतकालीन ओलम्पिक तथा पैरालम्पिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार रजत पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ रुपये के स्थान पर 3 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपये के स्थान पर 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एशियाई खेलों तथा पैरा एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए स्वर्ण पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए इसे 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये कर दिया गया है। रजत पदक विजेताओं को अब 30 लाख रुपये के स्थान पर 2.50 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये के स्थान पर 1.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्र मण्डल खेलों तथा पैरा राष्ट्र मण्डल खेलों में गौरव हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी संशोधित पुरस्कार योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए 50 लाख रुपये के स्थान पर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को 30 लाख रुपये के स्थान पर 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपये की जगह 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नई खेल नीति का उद्देश्य खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार राशि में यह वृद्धि राज्य सरकार की खेलों को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को और अधिक अवसर प्राप्त होंगे जो राज्य में खेलों के समग्र विकास में योगदान देगा।

कांग्रेस सरकार मजबूती के साथ करेगी अपना कार्यकाल पूराःप्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनावों के परिणामों से भाजपा को ज्यादा खुश होने की जरूरत नही है। उनका 400 पार का नारा देश के लोगों ने पूरी तरह ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लोकसभा की चारों सीटों पर भले ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है पर विधानसभा के उप चुनावों में कांग्रेस को छः में से चार सीटों पर जीत हासिल हुई है इससे साफ है कि प्रदेश के लोग कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े है।

प्रतिभा सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है और कांग्रेस इसका पूरा सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत में है और पूरी मजबूती के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी।

प्रतिभा सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस बयान को पूरी तरह हास्यास्पद बताया है जिसमें वह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से त्यागपत्र की मांग कर रहें है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनके कार्यकाल में कांग्रेस ने मण्डी संसदीय उप चुनाव के साथ तीन विधानसभा उप चुनावों में भाजपा को 4-0 से करारी शिकस्त दी थी तो उस समय उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र क्यो नही दिया था। उन्होंने कहा कि नैतिकता का पाठ जयराम ठाकुर के मुंह से अच्छा नही लगता क्योंकि नैतिकता भाजपा के पास है ही नही। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लोगों ने दलबदल व धनबल को पूरी तरह ठुकरा दिया है।

प्रतिभा सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से न तो निराश होने और न ही अपने मनोबल में कोई भी कमी न लाने का आहवान करते हुए कहा है कि उन्हें आगामी 3 विधानसभा उप चुनावों में पार्टी की जीत के लिये अभी से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और उन्हें पूरे उत्साह के साथ प्रदेश कांग्रेस सरकार की लोकप्रिय नीतियों व जनहित के निर्णयों के साथ लोगों के बीच जाना है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह नई दिल्ली में 8 जून को होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भाग लेंगी। इस दौरन वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगी।

सेब बागवानी में एच.पी.एम.सी. का महत्वपूर्ण योगदानःजगत सिंह

शिमला/शैल। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं विधायन निगम (एच.पी.एम.सी.) की स्वर्ण जयंती के अवसर पर सेब बागवानी में एच.पी. एम.सी. के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि एच.पी.एम.सी. की स्थापना 10 जून, 1974 को शिमला में की गई थी, जिसका उद्देश्य सेब एवं अन्य फल बागवानों के हितों की रक्षा, विपणन सुविधाएं, फल प्रसंस्करण एवं पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाएं प्रदान करना था। गत 50 वर्षों में एच. पी.एम.सी. ने सेब बागवानी की उन्नति में उत्प्रेरक का काम किया है। उन्होने कहा कि एच.पी.एम.सी. फल प्रसंस्करण एवं पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के क्षेत्र में देश भर में पिछले 5 दशक से अग्रणी संस्थान है।

बागवानी मंत्री ने कहा कि निगम ने वर्ष 1980 में परवाणू में देश का पहला एप्पल जूस कंसंट्रेट संयंत्र स्थापित किया था। एच.पी.एम.सी. ने 1970 एवं 1980 के दशक में दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई में शीत गृहों तथा प्रदेश में 4 शीत गृहों (कोल्ड स्टोर) का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त एच.पी.एम.सी. ने देश में पहली बार बोतलबंद जूस का उत्पादन एवं विपणन प्रारंभ किया।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि एच.पी.एम.सी. प्रतिवर्ष प्रदेश के लगभग 30,000 सेब बागवानों से मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सी ग्रेड सेब की सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर खरीद कर परवाणू, पराला एवं जड़ोल (सुंदरनगर) स्थित अपने फल प्रसंस्करण संयंत्रों में एप्पल जूस कंसंट्रेट का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त एच.पी.एम.सी. टेट्रा पैक जूस, जैम, स्क्वैश, एप्पल साइडर विनेगर एवं अचार आदि का उत्पादन भी करता है।

बागवानी मंत्री ने कहा कि एच. पी.एम.सी. सेब बागवानों को विश्वस्तरीय पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक से लैस 10 ग्रेडिंग पैकिंग हाउस एवं 5 सी.ए. स्टोर की सुविधा उचित दरों पर उपलब्ध करवा रहा है। बागवानी मंत्री ने एच. पी.एम.सी. के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर एच.पी.एम.सी. के प्रबन्ध निदेशक सुदेश मोखटा तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश में उप-चुनावों के लिए अनुसूची तथा दिशा-निर्देश जारी

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने सात राज्यों में 13 विधानसभा क्षेत्रों के रिक्त स्थानों के लिए उप-चुनावों की अनुसूची जारी की है। इसके अतिरिक्त बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में उप-चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जिला कांगड़ा के देहरा, जिला हमीरपुर के हमीरपुर तथा जिला सोलन के नालागढ़ में चुनाव आयोजित होंगे।

हिमाचल प्रदेश में उप-चुनावों के लिए विस्तृत अनुसूची इस प्रकार है: राजपत्रित अनुसूची 14 जून, 2024 (शुक्रवार) को जारी की जायेगी तथा नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 21 जून, 2024 (शुक्रवार) होगी। नामांकन पत्रों की छंटनी 24 जून, 2024 (सोमवार) को होगी तथा नामांकन वापिस लेने की अन्तिम तिथि 26 जून, 2024 (बुधवार) होगी।

उन्होंने बताया कि चुनाव 10 जुलाई, 2024 (बुधवार) को आयोजित किए जायेंगे जबकि 13 जुलाई, 2021 (शनिवार) को मतगणना की जाएगी। 15 जुलाई, 2024 (सोमवार) से पूर्व चुनाव पूर्ण किये जायेंगे।

मनीष गर्ग ने इस अवधि के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन की महत्तता पर बल दिया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा हितधारकों से निष्पक्ष तथा शांतिमय चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश तथा निर्देश जारी किए जाएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संबंधित जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व को प्रदेश में नकारा: बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा ने हिमाचल में लोक सभा की चारों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। इसको लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं में अद्भुत जोश देखने को मिला।

कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी रैलियां निकाली गई, पीएम मोदी के नारों से हिमाचल गूंज उठा।

इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल शिमला मुख्यालय में रहे जहां सुबह से उन्होंने चुनावी खाके पर नजर गड़ाये रखी थी और पूरे प्रदेश के आंकड़ों को एकत्रित किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा कांगड़ा संसदीय सीट 251895, मंडी 73482, हमीरपुर 178056 और शिमला 90548 के अंतर से जीती।

उन्होंने कहा की देश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व को पूरा आशीर्वाद दिया है, एनडीए को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यह अपने आप में ऐतिहासिक है। यह बड़ा रिकॉर्ड है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पीएम मोदी को जन मत प्राप्त हुआ है, इसके लिए जनता का आभार एवं अभिनंदन।

उन्होंने कहा की जनता ने कांग्रेस के नेतृत्व को प्रदेश में नकारा है, कांग्रेस लोक सभा की एक भी सीट नहीं जीत पाई इससे साफ है की जनता का अटूट विश्वास पीएम मोदी में है न की प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार में। मुख्यमंत्री सुक्खू को इस मौके पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।

बिंदल ने कहा की इस बड़ी जीत का पूर्ण श्रेय पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देना चाहिए। एक बात शीशे की तरह साफ दिखती है की मुख्यमंत्री और उनकी आर्मी ने सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया और सत्ता के दम पर दादागिरी की। पर जनता ने उनको इनकी दादागिरी का जवाब दे दिया।

सुरेश कश्यप ने जीत दर्ज करने के बाद कहा की हिमाचल में मोदी मैजिक का असर दिखा और भाजपा ने चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। जीत के लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, इस जीत का श्रेय पीएम मोदी और भाजपा के देवतुल्य कार्यकताओं को जाता है।

जेपी नड्डा के केन्द्रीय मंत्री बनने पर बधाई

शिमला/शैल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल, महामंत्री त्रिलोक कपूर, बिहारी लाल शर्मा, डॉ सिकंदर कुमार, मुख्य प्रवक्ता राकेश जमवाल, मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा, त्रिलोक जमवाल, संदीपनी भारद्वाज, विनोद कुमार, जनक राज, हर्ष महाजन, इंदु गोस्वामी, विपिन सिंह परमार, बिक्रम ठाकुर, गोविंद ठाकुर, सुखराम चौधरी, रीना कश्यप, सूरत नेगी, वीरेंद्र कश्यप, लखविंदर राणा, राकेश शर्मा, संजय शर्मा, सुधीर शर्मा, लोकिंदर कुमार, दीपराज कपूर, दिलीप ठाकुर ने बधाई दी।

इसी के साथ नवनियुक्त सांसद सुरेश कश्यप, डॉ राजीव भारद्वाज, कंगना रानाउत एवं अनुराग ठाकुर ने भी उनको शुभकामनाएं दी।

जगत प्रकाश नड्डा ने 1978 में एबीवीपी से जुड़कर छात्र राजनीति शुरू की। इसके बाद 1991 से 1994 के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनकी पत्नी मल्लिका नड्डा भी 1988 से 1999 तक एबीवीपी की राष्ट्रीय महासचिव रहीं । 2014 में मोदी सरकार में मंत्री बनने से पहले वह नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के अध्यक्ष रहते पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2012 और 2018 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। वे पहली बार 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गये थे और 1994 से लेकर 1998 तक राज्य विधानसभा में पार्टी के नेता रहे। इसके बाद वे दुबारा 1998 में फिर विधायक चुने गये, इस बार उन्हें स्वास्थ्य और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। 2007 में उन्हें फिर से चुनाव जीतने का अवसर मिला और प्रेम कुमार धूमल की सरकार में उन्हें वन-पर्यावरण, विज्ञान व टेक्नालॉजी विभाग का मंत्री बनाया गया। 20 जनवरी 2020 को उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सितम्बर 2022 में जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया हैं।

उप-चुनावों में चार कांग्रेस व दो भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीते

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि छः विधानसभा क्षेत्रों के उप-चुनावों में चार कांग्रेस व दो भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते।

धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने 28066 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के देवेन्द्र सिंह जग्गी को हराया, जिन्हे 22540 मत प्राप्त हुये। निर्दलीय प्रत्याशी राकेश चौधरी को 10770, सतीश कुमार को 422 तथा नोटा को 482 मत मिले।

लाहौल-स्पिति विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुराधा ने 9414 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय डॉ. राम लाल मारकण्डा को हराया, जिन्हें 7454 मत प्राप्त हुए। भाजपा के रवि ठाकुर को 3049 तथा नोटा को 76 मत मिले।

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने 29529 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के राजेन्द्र सिंह राणा को हराया, जिन्हें 27089 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रविन्द्र सिंह डोगरा को 334, निर्दलीय प्रत्याशियों अनिल राणा को 134 व शेर सिंह को 71 राजेश कुमार 46, तथा नोटा को 241 मत मिले।

कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक शर्मा ने 36853 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के दविन्द्र कुमार भुट्टो को हराया, जिन्हें 31497 मत प्राप्त हुए। निर्दलीय प्रत्याशी चंचल सिंह को 300 तथा राजीव शर्मा को 234 तथा नोटा को 341 मत मिले।

विधानसभा क्षेत्र गगरेट से कांग्रेस के राकेश कालिया ने 35768 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के चैतन्य शर्मा को हराया, जिन्हें 27281 मत प्राप्त हुए।

निर्दलीय अमित वशिष्ट को 570, अशोक सौंखला को 323 तथा मनोहर लाल शर्मा को 288 तथा नोटा को 606 मत मिले।

विधानसभा क्षेत्र बड़सर से भाजपा के इन्द्रदत्त लखनपाल ने 33086 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के सुभाष चन्द को हराया, जिन्हें 30961 मत प्राप्त हुए।

निर्दलीय प्रत्याशी विशाल कुमार को 452 तथा नोटा को 323 मत मिले।

संसदीय क्षेत्रों के परिणाम घोषित

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की चारों संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवारों को जीत प्राप्त हुई।

कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉ. राजीव भारद्वाज को 632793 व कांग्रेस उम्मीदवार आनन्द शर्मा को 380898 वोट मिले, जबकि 6372 ने नोटा का बटन दबाया।

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को 607068 व कांग्रेस के सतपाल रायजादा को 424711 वोट मिले, जबकि 5178 ने नोटा को चुना।

मंडी संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्यशी कंगना रनौत 537022 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 462267 वोट प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त 5645 ने नोटा का विकल्प चुना।

शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सुरेश कश्यप को 519748 जबकि कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी को 428297 वोट मिले और 5930 ने नोटा का विकल्प चुना।

नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की बधाई:जयराम

शिमला/शैल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी वक्तव्य जारी करके नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह भाजपा समेत पूरे देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने तीसरी बार भाजपा और एनडीए को अपार जनसमर्थन देने के लिए देशवासियों का भी आभार व्यक्त किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक होगा। तीसरे कार्यकाल के लिए नरेन्द्र मोदी ने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए है वह सभी बाकी के दो कार्यकाल के लक्ष्यों की तरह आसानी से निर्धारित समय के भीतर प्राप्त होंगे। जयराम ठाकुर भी दिल्ली पहुंच कर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने पहले ही साफ़ कर दिया है कि तीसरा कार्यकाल बाक़ी दोनों कार्यकाल से अलग और ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। इस दौरान बड़े फ़ैसले देखने को मिलेंगे। देश के लोग नरेन्द्र मोदी के हर बड़े फ़ैसले के साथ खड़े हैं। उनके कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर हैं। नरेन्द्र मोदी की सरकार सबका साथ-सबका विकास के लक्ष्य के साथ काम करेगी और देश के हर वंचित वर्ग के उत्थान के लिए काम करेगी। नरेन्द्र मोदी की यह सरकार देश के गरीब, युवा, नारी और किसान के विकास के लिए समर्पित रहेगी। इनके उत्थान और सशक्तीकरण के लिए काम करेगी। देशवासियों के सहयोग से हम विकसित भारत के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जिससे निर्धारित समय में भारत के विकसित देश बन सके।

आयोग ने हिंसा मुक्त चुनाव राष्ट्रपिता को समर्पित किए

शिमला। निर्वाचन आयोग ने भारत की माननीय राष्ट्रपति को 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम सौंपने के बाद राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के ग्रेजुएट और टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर, जहां तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू नहीं रहेगी, वहां ग्रेजुएट और टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों में विधान परिषद के द्विवार्षिक/उप-चुनावों के कारण एमसीसी लागू है।

राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आयोग का ब्यान है कि 'हम यहां राष्ट्र द्वारा हमें सौंपे गये पवित्र कार्य, 18वीं लोकसभा के आम चुनाव सम्पन्न कराने के बाद राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़े हैं। हम भारत के लोगों की इच्छा को लगभग अहिंसक तरीके से उत्प्रेरित करने के बाद अपने दिल में विनम्रता लिए हुए यहां खड़े हैं।

'लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है', यह वह स्पष्ट प्रतिबद्धता थी जिसके साथ 16 मार्च, 2024 को 18वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा की गई थी। चुनावी प्रक्रिया को हिंसा से मुक्त रखने की इस प्रतिज्ञा के पीछे हमारी प्रेरणा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उन्होंने इंसान के बीच समानता की वकालत की और सभी के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की वकालत की।

महात्मा के विचारों में, वयस्क मताधिकार 'सभी प्रकार के वर्गों की सभी उचित आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है'। मतदान केन्द्रों पर उत्सव के मूड में लंबी कतारें और मतपत्र के माध्यम से अपने भविष्य का फैसला करने का दृढ़ संकल्प महात्मा के पोषित आदर्शों और भारत की सभ्यतागत विरासत का प्रमाण था।

आयोग ने पूरे दिल, दिमाग और पूरी ईमानदारी के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है कि '' सबसे आम भारतीय का मताधिकार किसी भी कीमत पर नकारा न जाए, बल्कि इसे सख्ती से सक्षम बनाया जाए'' कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रतियोगिता लोकतांत्रिक अधिशेष पैदा करे और हमारे विशाल परिदृश्य में शामिल करोड़ों लोगों के गहन कार्यों में किसी भी रूप में हिंसा की थोड़ी सी भी छाया पड़ने की अनुमति न हो। जम्मू-कश्मीर और मणिपुर समेत भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने परिपक्व आचरण से एक मिसाल कायम की है जो भविष्य के लिए शुभ संकेत है। शांति और विकास का रास्ता गोली नहीं बल्कि मतपत्र है।

हम इस शपथ के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग की राष्ट्र के प्रति सेवा, जो अब अपने 76वें वर्ष में है, अडिग समर्पण के साथ जारी रहेगी। हमने अफवाहों और निराधार संदेहों के साथ चुनावी प्रक्रिया को दूषित करने के सभी प्रयासों को खारिज कर दिया, जो अशांति भड़का सकते थे। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपार आस्था रखने वाले आम आदमी की 'इच्छा' और 'बुद्धि' की जीत हुई है। हम नैतिक और कानूनी रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव आयोजित करके हमेशा इसी भावना को बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

तीनों उपचुनावों में निर्दलीयों की उम्मीदवारी बहाल रखना भाजपा के लिये बना चुनौती

- संभावित विरोध और विद्रोह को शान्त रखना होगी बड़ी चुनौती
- नड्डा और अनुराग पर भी आयेगी जिम्मेदारी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय मंत्री परिषद में इस बार कोई स्थान नहीं मिला है जबकि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इस समय

गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री परिषद में स्वास्थ्य मंत्री बनाये गये हैं। उनके मंत्री बनने से प्रदेश को प्रतिनिधित्व न मिलने का मुद्दा भले ही भाजपा में बड़ा सवाल नहीं बना है लेकिन सता रूढ़ कांग्रेस ने इस पर सवाल अवश्य खड़े किये हैं। प्रदेश की राजनीति में यह सवाल बराबर बना हुआ है कि अनुराग ठाकुर को इस बार मंत्री परिषद में स्थान क्यों नहीं मिल पाया। इसके संभावित कारणों पर दबी जुबान से यह आवश्यक सुनने को मिल रहा है कि जब भाजपा लोकसभा की चारों सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही है तो फिर विधानसभा के लिये हुये छः उपचुनावों में से चार पर कैसे हार गयी? जबकि जिन चार स्थानों पर कांग्रेस विधानसभा के लिये जीत गयी और उन्हीं स्थानों पर लोकसभा के लिये भाजपा जीती है। एक ही विधानसभा में एक ही समय में इस तरह का अलग मतदान कई सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा की ओर से विधानसभा उपचुनाव हारने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। इन उपचुनावों में चार तो ऊना और हमीरपुर जिलों में ही है जो कि अनुराग ठाकुर का अपना लोकसभा चुनाव क्षेत्र है। विधानसभा के लिये हुये उपचुनावों की स्थिति राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के बागियों द्वारा भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के कारण पैदा हुई थी। क्योंकि क्रॉस वोटिंग के बाद यह बागी भाजपा में शामिल हो गये थे। कांग्रेस ने भाजपा के इस आचरण की सुक्खू सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस की संज्ञा दी थी। पूरे चुनाव प्रचार में भाजपा पर धनबल से सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस कथित लोटस ऑपरेशन की व्यूह रचना में भाजपा हाईकमान की पूरी सहमति रही है। क्योंकि भाजपा हाईकमान ने इन बागियों और तीनों निर्दलीयों को विधानसभा उपचुनाव के लिये अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। इन लोगों को उम्मीदवार बनाना भाजपा को अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए आवश्यक था। स्वभाविक है कि इस सबके लिये प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी अवश्य विश्वास में लिया गया होगा। अनुराग ठाकुर उस समय केंद्र में मंत्री थे। इस नाते यह सब कुछ उनके संज्ञान में भी अवश्य रहा होगा। फिर अनुराग या प्रदेश के किसी भी अन्य नेता ने इस दल बदल पर कभी कोई सवाल भी नहीं उठाया है। लेकिन अन्त में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में ही चार में से तीन स्थान हार जाना अपने में कई सवाल तो पैदा करता ही है। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी सभाओं में सुक्खू सरकार के भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। इस परिदृश्य में आने वाले दिनों में प्रदेश भाजपा के समीकरणों में भी कई बदलाव देखने को मिले तो इनमें आश्चर्य नहीं होगा। अब प्रदेश के तीनों निर्दलीयों के क्षेत्रों में भी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इन निर्दलीयों के भाजपा में शामिल होते ही हाईकमान ने उन्हें उपचुनाव के लिये उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ समय से इन क्षेत्रों में भी भाजपा के पुराने लोगों में निर्दलीयों को प्रत्याशी बनाये जाने पर रोष पनपने के समाचार लगातार सामने आ रहे हैं। यह भी फैल रहा है की संभावित विद्रोह को देखते हुये शायद इन लोगों को प्रत्याशी बनाने पर पुनः विचार हो। क्योंकि इस तरह के समाचारों का प्रदेश भाजपा नेतृत्व की ओर से कोई खण्डन भी नहीं आया है। ऐसे में इन तीन उपचुनाव में इन निर्दलीयों की उम्मीदवारी कायम रखना और उनके खिलाफ पार्टी में कोई विरोध या विद्रोह न उभरने देना प्रदेश नेतृत्व की कसौटी बन जायेगा। संयोगवश इन तीन

उपचुनावों में से दो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से ही है। अनुराग ठाकुर यहां के सांसद है तो केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। इस वस्तुस्थिति में यह उपचुनाव अनुराग और नड्डा के लिये भी चुनौती होंगे।

किस काम के लिए लिया जा रहा कर्ज जबाव दे सरकार:जयराम

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार देश के किसानों,

युवाओं, ग़रीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले फ़ैसले में किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने 'पीएम किसान सम्मान निधि' की 17वीं किस्त के रूप में लगभग रुपये 20 हजार करोड़ से अधिक की राशि से 9 करोड़ से अधिक किसानों के देने के निर्णय की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री का आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मोदी 3.0 की सरकार इसी तरह से देश के लोगों के विकास के काम करती रहेगी। आने वाले समय में और बड़े फ़ैसले तथा जनहितकारी योजनाएं ज़मीन पर उतरती दिखाई देंगी।

जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में क़ानून-व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ऐसी-ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक दिन में तीन-तीन लोगों की बेरहमी से हत्या हो रही है। सरकार, पुलिस और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सुक्खू सरकार ने हिमाचल के लोगों कि जीवन को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। जब से कांग्रेस सत्ता में आयी है तभी से अपराधियों के हौसलें बुलंद हैं। एक अपराध पर कारवाई न करने से ही अपराधियों के हौंसले बुलंद हो रहे हैं। कहा कि सरकार जिस तरह से आँख मूंदकर बैठी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकार को सरकार की तरह काम करना होगा। आम आदमी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो यह भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। उन्होंने से मुख्यमंत्री से हाल में हुई आपराधिक घटनाओं पर सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग की।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चुनाव ख़त्म हो गये, आचार संहिता हट गयी लेकिन सरकार अभी अपने नींद से नहीं जागी। विकास के काम जस के तस पड़े हैं। बस अख़बारों के माध्यम से सरकार के क़र्ज़ पर क़र्ज़ लेने का पता चलता है। इस महीनें फिर से सरकार ने 1200 करोड़ का क़र्ज़ लिया है। इसी वित्तीय वर्ष में सरकार 2900 करोड़ का क़र्ज़ लें चुकी है। जबकि दिसम्बर तक क़र्ज़ की लिमिट 6200 करोड़ रुपए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या क़र्ज़ लेकर ही सरकार चलेगी। कहा कि सत्ता में आने के पहले कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा जाता था कि हम आय के नये साधन बनायेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद से रिकॉर्ड स्तर पर क़र्ज़ ले रहे हैं। जबकि न तो सरकार ने अपने चुनावी वादे पूरे किये हैं और न ही विकास के कार्य कर रही है। ऐसे में यह क़र्ज़ किस काम के लिए लिया जा रहा है सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।